

भारत का वमिानन उद्योग

प्रलमिस के लयि:

भारत का वमिानन उद्योग, वमिानन टरबाइन ईधन, [RCS-UDAN](#), राष्ट्रीय नागरकि उड्डयन नीत- 2016, सतत् वमिानन ईधन

मेन्स के लयि:

भारत में वमिानन उद्योग की स्थति, भारत में वमिानन क्षेत्र को पुनः सक्रयि करने के उपाय

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

[भारत के वमिानन उद्योग](#) में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। हालाँकि इस दुरुत वसितार ने **अनुभवी पायलटों की गंभीर कमी** सहति महत्त्वपूर्ण मुद्दों को भी उजागर कयि है।

भारत में वमिानन उद्योग की स्थति:

- **परचय:** भारत का वमिानन उद्योग एक सामूहकि क्षेत्र है जो देश के भीतर नागरकि उड्डयन के सभी पहलुओं को शामिल करता है।
 - इसमें वभिनिन घटक शामिल हैं, जैसे [एयरलाइंस](#), [वमिान पत्तन](#), [वमिान नरिमाण](#), [वमिानन सेवाएँ](#) और [नयामक प्राधकिरण](#)।
- **स्थति:**
 - भारत **वशिव का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू वमिानन बाज़ार** बन गया है। भारत के वमिान पत्तन की क्षमता के आधार पर वर्ष 2023 तक सालाना 1 अरब यात्राओं के परचालन की उम्मीद है।
 - **उद्योग और आंतरकि व्यापार संवर्द्धन वमिान (Department for Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT)** द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, भारत के हवाई परविहन क्षेत्र (हवाई माल ढुलाई समेत) में **FDI प्रवाह अप्रैल 2000 से दसिंबर 2022 के दौरान 3.73 बलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।**
- **संबद्ध चुनौतयिाँ:**
 - **बुनयिादी ढाँचे की बाधाएँ:**
 - **हवाई अड्डों पर भीडभाड:** मुंबई और **दलिली** सहति भारत के कई प्रमुख हवाई अड्डों को व्यापक भीड का सामना करना पडता है, जसिसे **वलिंब एवं परचालन अक्षमता** जैसी स्थति उत्पन्न होती है।
 - **सीमति क्षेत्रीय कनेक्टविटी:** हालाँकि प्रमुख शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, छोटे शहरों और क्षेत्रों में प्रायः पर्याप्त हवाई अड्डा बुनयिादी ढाँचे और हवाई कनेक्टविटी का अभाव होता है।
 - **उच्च परचालन लागत:**
 - **वमिानन टरबाइन ईधन (ATF)** और हवाई अड्डे के शुल्क पर उच्च कर परचालन, लागत में वृद्धि में योगदान करते हैं।
 - कुछ भारतीय राज्य **जेट ईधन पर 30% तक कर** वसूलते हैं, जसिसे छोटे उड्डान मार्ग छोटी एयरलाइन्स के लयि अलाभकारी हो जाते हैं।
 - **पायलट की कमी:**
 - भारत में एयरलाइंस प्रायः अनुभवी पायलटों की भरती करने और उन्हें बनाए रखने के लयि संघर्षरत रहते हैं, जसिसे व्यवधान उत्पन्न होता है और शर्म लागत में वृद्धि होती है।
 - वमिान ऑर्डरों में बढोतरी, कुल 1,100 से अधिक नए वमिानों के कारण उड्डान चालक दल के हज़ारों सदस्यों की आवश्यकता है।
 - हालाँकि भारत में **पायलट प्रशकिषण की औसत लागत लगभग 1 करोड रुपए है।**
 - एयरलाइंस प्रायः वभिनिन बहाने से कैंडेट पायलटों से अतरिकित शुल्क वसूलते हैं, जसिसे वत्तीय बोझ काफी बढ जाता है।
 - **सुरक्षा खतरे:** [आतंकवाद और अपहरण](#) से परे वमिानन बुनयिादी ढाँचे को अब [साइबर खतरों](#) का सामना करना पड रहा है जो संचालन को बाधति कर सकता है और यात्री डेटा को उजागर कर सकता है।

- अन्य चुनौतियाँ: आलोचकों का तर्क है कि भारतीय वायु सेना के डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा मानकों के प्रबंधन के कारण बड़ी संख्या में नागरिक पायलटों को नौकरी से निकाल दिया गया है।
 - इसके अलावा उड़ान प्रशिक्षण केंद्र के संचालन से जुड़ी कई चुनौतियाँ हैं, जो स्वतंत्रता-पूर्व समय के नियमों को लागू करने वाले अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार के कारण और भी बढ़ गई हैं।
- संबंधित सरकारी पहल:
 - घरेलू रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सेवाओं के लिये वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई।
 - कषेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने और नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करने के लिये टयोर-II एवं टयोर-III शहरों में असेवति तथा कम सेवति हवाई अड्डों के हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये RCS-UDAN को लॉन्च किया गया था।
 - राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016

भारत में विमानन क्षेत्र को पुनः सक्रिय करने के उपाय:

- पर्यावरण-अनुकूल पहल: उत्सर्जन एवं परिचालन लागत को कम करने, कम दूरी की उड़ानों के लिये इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड विमानों के विकास और प्रयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
 - साथ ही उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये सतत विमानन ईंधन (SAF) और कार्बन ऑफसेट कार्यक्रमों के प्रयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
 - जून 2021 में स्पाइसजेट ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) के तत्वावधान में वर्ष 2030 तक 100 मिलियन घरेलू यात्रियों के लिये SAF ब्लेंड आधारित उड़ान के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की।
- रख-रखाव हेतु डिजिटल ट्विन्स:
 - विमान की आभासी प्रतिकृतियाँ बनाने, पूर्वानुमानित रख-रखाव को संभव करने और डाउनटाइम को कम करने के लिये डिजिटल ट्विन तकनीक को लागू करने की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP):
 - विश्वस्तरीय सुविधाएँ सुनिश्चित करते हुए हवाई अड्डे के बुनियादी ढाँचे के विकास में सह-निवेश हेतु सरकार और नजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
 - भारत में PPP हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 5 से बढ़कर वर्ष 2024 में 24 हो जाने की संभावना है।
- पायलट की कमी का समाधान:
 - विमानन स्कूलों और अकादमियों के सहयोग से सब्सिडी आधारित पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करने की आवश्यकता है।
 - यह इच्छुक एविएटर्स के लिये पायलट प्रशिक्षण को और अधिक कफायती बना सकता है।
- विमानन पर्यटन पैकेज: भारत को विमानन पर्यटन का केंद्र बनाने के लिये विमानन उद्योग को पर्यटन उद्योग के साथ मलिकर अभिनव विमानन-आधारित पर्यटन पैकेज तैयार करने की आवश्यकता है, जो सुरम्य उड़ानें, साहसिक अनुभव और हवाई फोटोग्राफी पर्यटन की पेशकश कर सकें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. सार्वजनिक-नजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अधीन संयुक्त उपकरणों के माध्यम से भारत में विमान पततनों के विकास का परीक्षण कीजिये। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं? (2017)